सड़कें, पुल, स्कूल, कॉलेज व अस्पताल तो बनते नहीं, भाजपा का पंच सितारा दफ्तर बन कर तैयार

फ़रीदाबाद (म.मो.) आम जनता के उपयोग में आने वाली सड़कें हों या मंझावली का यमुना पुल हो चाहे जर्जर हो चुकी स्कूल इमारतें, उनकी सुध लेने की फुर्सत कभी खट्टर को मिली नहीं लेकिन तुर्त-फुर्त ज़िला भाजपा का कार्यालय बनवा कर 25 मई को उसका उद्घाटन कर दिया।

सेक्टर 15 के बेशकीमती 1250 गज़ के प्लॉट में बना यह चार मंजिला भव्य भवन तमाम भैतिक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित है। इस प्लॉट का बाजार भाव दो लाख रुपये प्रति गज़ से कम नहीं है। यानी कि सीधे-सीधे 25 करोड़ का प्लॉट। यह बात अलग है कि जब अपनी सरकार हो तो 25 करोड़ रुपये तो क्या 25 पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं। 'हूडा' के इस प्लॉट की कीमत खट्टर जो चाहें तय कर सकते हैं। तय की गई वह रकम भी 'हूडा' के उन भ्रष्ट कर्मचारियों के जिम्मे डाल दी गई होगी जो सुबह से शाम तक जनता को मूंडने में लगे रहते हैं।

रही बात आलीशान भवन निर्माण करने की तो सत्तारूढ़ दल के लिये यह कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इस तरह के काम तो भाजपा आज कल हर ज़िले में कर रही है। आज नहीं करेगी तो कब करेगी? रोहतक वाले कार्यालय का निर्माण उस ठेकेदार के जिम्मे था जिसने वहां रेलवे का एक बड़ा काम किया था। इसी तरह सम्हालका के निकट पट्टी कल्याणा में भी आरएसएस का कार्यालय निर्माण उन भ्रष्ट अफ़सरों के जिम्मे था जो गुड़गांव, सोनीपत व पानीपत में जनता को लूटने में जुटे थे।

उन्हीं नक्शे कदम पर चलते हुए यहां का दफ्तर निर्माण भी आसानी से और तुर्त-फुर्त हो गया। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े इन तमाम दफ्तरों का प्रेरणाश्रोत दिल्ली के कनॉटप्लेस में हजार करोड़ की लागत से बना केन्द्रीय भाजपा कार्यालय है। जब वहां इतना भव्य आलीशान कार्यालय भवन बन सकता है तो भला फ़रीदाबाद वाले भाजपाई कैसे पीछे रह सकते थे? यहां तो इतने बड़े-बड़े मगरमच्छ पलते हैं जो 200 करोड़ डकार कर फ़ाइलें तक फूक देते हैं। यहां की हर मलाईदार पोस्ट पर तैनाती पाने के लिये क्लर्क से लेकर अफ़सर तक लाखों रुपया हथेली पर लिये फिरते हैं। ऐसे में भला कार्यालय निर्माण हेतु धन का अभाव कैसे हो सकता था?

इस अवसर पर आये खट्टर व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष व ओम प्रकाश धनखड़ ने बीते आठ साल में, उनकी सरकार द्वारा किये गये कार्यों का बखान करते हुए जम कर झूठ बोला।

उन्होंने जो नहीं बताया:

1. जन, पशुधन, का नमूना देखना हो तो हर शहर की हर सड़क पर गौ माताओं के झूंड के झूंड देखे जा सकते हैं जिनकी वजह से आये दिन कहीं न कहीं कोई न कोई घातक दुर्घटना होती रहती है। खेतो में खड़ी फ़सलों को रात भर में ही ये झूंड साफ़ कर देते हैं।

2. खेती से किसान का कौन सा जोखिम इन्होंने समाप्त कर दिया किसी को मालूम नहीं। हां, इतना जरूर मालूम है कि फ़सल बीमा योजना के नाम पर किसानों से जबरन वसूली करके बीमा कम्पनी को मालामाल कर दिया। ट्रैक्टर व ईंजन में लगने वाला डीजल 96 रुपये लीटर करके किसान का कौन सा भला कर दिया? खाद के भाव तो बढ़ाये सो बढ़ाये, उसे लेने के लिये भी रात-दिन लम्बी लाइनें लगी रही।

3. महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार द्वारा उठाया गया कोई कदम धरातल पर तो कहीं नज़र आया नहीं।

4.महामारी पर सरकारी नियंत्रण को पिछले साल जनता ने बखूबी भुगता है। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर सोने के भाव बिक रहे थे, निजी अस्पतालों ने पूरी बेदर्दी से जनता को जम कर लूटा था। मरने के बाद शवों को जलाने के लिये लम्बी कतारें भी इसी राज में देखने को मिली।

5. विश्वस्तरीय ढांचाग्रस्त विकास के नाम पर शहर की टूटी सड़कें, उफनते सीवरों का बहता सड़ा पानी व जलभराव में डूबे अंडरपास विकास का बढ़िया चित्रण करते रहे।

6. रोजगार के नाम पर भयंकर बेरोजगारी भी इसी काल में देखने को मिली। खेल नीति ऐसी बढ़िया कि खेलने को मैदान नहीं और जो हैं भी उनमें घूसने का टैक्स लगा दिया।

7. आवास योजनाओं के नाम पर संघी बिचौलियों ने जिस प्रकार जनता को लूटा है उसके आंकड़े समय-समय पर **'मज़दूर मोर्चा'** द्वारा प्रकाशित किये जा चुके हैं। बिजली आपूर्ति की दशा कभी भी संतोषजनक नहीं रही। महंगी बिजली के साथ-साथ आपूर्ति की अनिश्चितता ने सदैव ही उपभोक्ताओं को परेशान रखा है।

अपनी इन झूठी उपलब्धियों का वर्णन करने के लिये भाजपा की ओर से एक छोटी सी पुस्तिका भी छाप कर बड़े पैमाने पर वितरित की गई। इसमें उस सेना के सशक्तिकरण की बात कही गई है जिसमें दो लाख पद आज के दिन खाली पड़े हैं। कशमीर से धारा 370 हटाने को उपलब्धि तो बताया लेकिन यह नहीं बताया कि वहां कितने लोगों ने जाकर प्लॉट खरीद लिये और कितनी दुल्हने वहां से ब्याह कर लाई गई?

भाजपा कार्यालय छह माह में बनकर तैयार, हार्डवेयर से प्याली तक की रोड तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बनी।

बारिश ने फ़िर धोयी शहर की 'स्मार्टनेस'

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के रख-रखाव के लिये नगर निगम द्वारा तो हजारों करोड़ रुपये बहाये ही जाते हैं, बीते करीब सात साल से स्मार्ट सिटी के नाम से ही हजारों करोड़ रुपये सड़कें खोदने, नालियां बनाने व रंग-रोगन आदि पर अलग से स्वाहा कर दिये जाने के बावजूद शहर की स्थिति जरा सी बारिष में अस्थिर हो गई। पुरानी एवं कच्ची बस्तियों की बात तो छोड़ ही दीजिये, तमाम नये बने पॉश सेक्टरों की हालत भी काफ़ी दयनीय हो गई थी। शायद ही कोई ऐसी सड़क अथवा गली बची हो जिसमें चार से 12 इंच तक पानी न भरा हो। तमाम सीवर भी उफ़ान मार कर इस जल भराव में अपना योगदान दे रहे थे।

हमेशा की तरह राष्ट्रीय राजमार्ग भी जल भराव के चलते जाम का शिकार हुआ। बाटा मोड़, अजरोंदा मोड़ तथा ओल्ड के चौंक हमेशा की तरह पानी में इस कदर डूब गये कि छोटे वाहनों का निकलना दूभर हो गया। इनके फंस जाने से बड़े वाहन भी इनके पीछे कतारों में लग गये। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, हर साल 10 से 20 बार तक यह सब होता आ रहा है। हर बार प्रशासन इनको ठीक करने के आश्वासन देता है, आश्वासनों को पूरा करने के लिये भारी-भरकम खर्च भी किया जाता है। लेकिन हर बारिष में इनके आश्वासन तथा बजट बरसाती पानी में बह जाते हैं।

अंडरपास दो दिन बंद रहे

शहर के दो रेलवे अंडरपास-पहला राजमार्ग से ग्रीन फील्ड कॉलोनी को जोड़ने वाला तथा दूसरा ओल्ड चौक से एनआईटी की ओर जाने वाला-इस बरसात से इस कदर लबालब भर गये कि सोमवार 23 तारीख को सुबह सात बजे से आवागमन पूरी तरह से ठप रहा।

इतना ही नहीं करीब सात बजे एक महिला शिक्षक ने अपनी वेगनआर (कार) से अंडरपास को पार करने की गुस्ताखी की तो वह बीच में ही ऐसी फंसी कि जान को जाखिम हो गया। पानी में डूबने से ईंजन तो बंद हुआ सो हुआ, इंटरलॉक भी जाम हो गया। कार में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। डूब मरने की स्थिति कोई बहुत दूर नहीं रह गई थी। ऐसे में इत्तफ़ाक से वह कार का पिछला (डिक्की वाला) दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई तो निकल कर अपनी जान बचा पाई। मर भी जाती तो इस बेरहम एवं भ्रष्ट शासन-प्रशासन को क्या फर्क पड़ने वाला था? सैंकड़ों-हजारों लोग रोज सड़कों पर मरते रहते हैं।

सोमवार की सुबह बंद हुआ यह अंडरपास मंगलवार को 9 बजे तक तो बिल्कुल बंद रहा, उसके बाद शाम तक धीरे-धीरे इसमें आवागमन शुरू हो पाया। विदित है कि रेलवे लाइन के पूरब तथा पश्चिम में बसने वाले इस शहर के दो भागों के बीच यातायात का यह एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसके बंद होने पर नीलम फलाईओवर का लम्बा चक्कर तो पड़ता ही है साथ में इस फ्लाईओवर पर भयंकर जाम की स्थिति बन जाती है।

कहने को इस अंडरपास से जल निकासी के लिये प्रशासन ने पूरा प्रबंध कर रखा है। पानी खींच निकालने के लिये बाकायदा डीजल ईंजन के साथ-साथ उसे चलाने के लिये भी किसी कामगार की तैनाती कर रखी है। लेकिन प्रशासनिक संवेदन हीनता के चलते न तो समय पर ईंजन चलता है और न ही पानी निकलता है। कारण? कारण स्पष्ट है कि मौके पर वक्त जरूरत न तो वहां ईंजन चलाने वाला कोई होता है और न ही ईंजन के लिये डीजल होता है। इन दोनों का प्रबंध करने में स्मार्ट सिटी के स्मार्ट प्रशासन को 10-20 घंटे तो लग ही जाते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा का शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा कि जब वह इस अंडरपास से दो-चार बार न गुजरती हों। इसके बावजूद उन्होंने कभी इस समस्या की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। सभी जानते हैं कि विधायक सीमा उन्हीं कामों की ओर ध्यान देती है जिनको कराने के लिये अच्छा-खासा टेंडर पास कराना हो। टेंडर जितना भारी-भरकम होगा, कमीशन भी मोटा ही मिलेगा। अंडरपास की जल निकासी से भला उन्हें कोई क्या दे देगा?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।